सराहनीय पहल, पर लक्ष्य अभी भी दूर

■ गुंजा कपूर
विश्लेषक, सीआरआईएसआईएल

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की एक सुस्पष्ट विशेषता रही है, वह अपने निर्णय की घोषणा स्वयं करते हैं। निर्णय लोकप्रिय हो जनता सरकार की नहीं मोदी जी की प्रशंसा करती है और जटिल, तो आलोचक भी सीधा उन्हीं पर निशाना साधते हैं। 8 नवम्बर, 2016 को रात 8 बजे जब प्रधानमंत्री ने जनता जनार्दन के बीच आकर 500 और 1000 रुपये की मुद्रा को रद्द करने का निर्णय सुनाया तो पक्ष ने इसे 'नोटबदली' कहा और विपक्ष ने इसकी तुलना आर्थिक नसबंदी से कर 'नोटबंदी' का नाम दे दिया।

भारत में गरीबी की समस्या इतनी प्राचीन है कि अब आर्थिक असमानता और गरीबी हमारी व्यवस्था का एक अविभाज्य अंग बन गई हैं। आश्चर्य की बात यह है कि भारत मुश्किल से मुश्किल समस्या का समाधान करने में सक्षम है, परंतु गरीबी को देश से निर्वासित करने में सदा मुंह की खाता है। कुर्सी पर डटे नेता और प्रशासन में बैठे बाबू चायप्यानी के नाम पर खूब काला धन बटोरते हैं। व्यापारी आय कर की चोरी हर साल करके सरकारी खजाने के साथ गद्दारी करते हैं, और गरीब इन सब का हिसाब अपनी जिद्दी गरीबी से चुकाते हैं। इसी गरीबी के विरुद्ध एक युद्ध छेड़ने की मुहीम मोदी जी ने नोटबदली द्वारा की। नोटबंदी का मुख्य लक्ष्य काले धन पर वार था। इसके अतिरिक्त, हमें अपेक्षा थी कि नकली मुद्रा का बाजार बैठ जाएगा जिससे आतंकवाद पर काबू पाना सरल हो जाएगा, नक्सलवादियों का वित्त पोषण भी समाप्त हो जाएगा और रिश्वत देने-लेने की कुप्रथा को हम मूल तौर पर जब्त कर पाएंगे। गौर करने वाली बात है, कि माननीय प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहीं भी राजनीतिक भ्रष्टाचार का जिक्र नहीं करा।

जब 86 प्रतिशत मुद्रा रद्द हुई तो आम नागरिकों को इन पांच परिणामों की अपेक्षा थी : काले धन के ढेर पर बैठे बाबुओं की नींद उड़ जाएगी, महंगाई गिरेगी, राजनीतिक दलों की भी कमर टूटेगी, आतंकवाद से निवृत्ति और भ्रष्टाचार के प्रति असहिष्णुता नये भारत की नई प्रथा होगी।

लाभ मिलना अभी बाकी

एक वर्ष उपरांत अफसोस की बात है कि भष्टाचार के विरुद्ध इस युद्ध में 100 से अधिक जानें गईं, पर काले धन के आदानप्रदान में कोई कमी नहीं हुई। आतंकवाद का खतरा आज भी देश पर मंडरा रहा है। नकली मुद्रा के जब्त होने के मामले आये दिन सामने आते हैं। जहां चौराहे पर चायप्यानी का बाजार गर्म है वहीं जमीन से जुड़े किसान, मिस्त्रीमजदूर, कारीगर, लघु व मध्यम व्यापारियों का संघर्ष जारी है। भले ही नोटबंदी का चुनावी असर सकारत्मक रहा हो, पर्याप्त आर्थिक लाभ प्राप्त करना बाकी है। जो यह तो स्पष्ट हो गया कि नोटबंदी के उद्देश्य और परिणाम संबद्ध नहीं थे, इस मुहीम को पूर्णतः असफल घोषित करना बौद्धिक ज्यादती होगी।

नोटबंदी जैसे निर्णय ऐतिहासिक होते हैं, और इनको उनके गंतव्य तक पहुंचाना हर नागरिक का कर्त्तव्य है। एक वर्ष उपरांत हमें बौद्धिक मंथन करने की आवश्यकता है। नोटबंदी भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रथम पहल है। नोटबंदी को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए हमें रचनात्मक तरीके अपनाने होंगे। नीतियों से सिर्फ सोच को दिशा मिलती है, उनको परचम तक पहुंचाने के लिए नीयत की भूमिका भी महत्त्वपूर्ण होती है। भारत के पास राजनीतिक नीयत है, निपुण नीति-निर्माता हैं, और 1.25 करोड़ नागरिकों का सहयोग है

जहां तक नोटबंदी के राजनीतिक आयाम की बात है, तो इस मुहीम से भारतीय जनता पार्टी को हर प्रकार का राजनीतिक लाभ प्राप्त हुआ। संगृहीत काले धन पर वार के चलते कई राजनीतिक दलों को 2017 के विधान सभा चुनाव में संसाधनों का अभाव सहना पड़ा। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में नोटबंदी को 92% समर्थन प्राप्त हुआ। जब मध्यम वर्ग और भ्रष्ट छुटभैयों को रुके सामने खड़े देखा, तो गरीबों को विश्वास हो गया कि उनके मन कि आवाज मोदी जी तक पहुंच गई।

परंतु क्या वाकई में गरीब के दर्द का मर्ज नोटबंदी थी? राजीव गांधी ने कहा था, भारत में भष्टाचार की यह हद है कि जब दिल्ली से एक रुपया चलता है, तो गरीब तक पहुंचते-पहुंचते 10 पैसे रह जाता है। क्या नोटबंदी ने इस रुपये की आबरू को नीलामी से बचाया? शायद नहीं। जुलाई-सितम्बर, 2017 तिमाही में बढ़ोतरी दर 5.7% थी। भले ही नोटबंदी ने काले धन के बहाव को न रोका हो परंतु इससे संग्रहीत काले धन पर वार अवश्य हुआ। इसके कारण घरेलू खपत कम हो गई, जिसका व्यापक असर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर पड़ा। जो अर्थशास्त्री आकड़ों की राजनीति करने को आतुर हैं, उनको याद दिलाना चाहेंगे कि ये आंकड़े भारत की वास्तविक स्तिथि को दर्शाते हैं, और अगर इस देश का सत्य आर्थिक सुस्ती है, तो यह ही सही; कम से कम हमें इतना तो पता चल गया कि हम विकास और प्रगति कि पंक्ति में कहां खड़े हैं, और कहां से कार्य आरंभ करना है।

नोटबंदी से संबंधित ये तीन सकारात्मक प्रभाव भी सामने आए : एक, डिजिटल लेन देन की प्रक्रिया में तेजी से बढ़ोतरी हुई। नीति आयोग के आंकड़ों के हिसाब से डिजिटल लेन देन में दुगुनी बढ़त हुई है। डिजिटल प्रक्रिया से भ्रष्टाचार पर नियंत्रण होगा तथा 'ईज ऑफ डूइंग विजनेस' के लिए एक निर्णयात्मक पहल होगी। दो, कर संग्रह में इजाफा, जिसका तात्पर्य है अधिक नागरिकों ने आय कर भरा और आगे भी भरेंगे। तीन, सामाजिक अनुशासन और नियमों का पालन न करने के अप्रत्याशित नतीजे का उदाहरण।

नोटबंदी जैसे निर्णय ऐतिहासिक होते हैं, और इनको उनके गंतव्य तक पहुंचाना हर नागरिक का कर्त्तव्य है। एक वर्ष उपरांत हमें बौद्धिक मंथन करने की आवश्यकता है। नोटबंदी भ्रष्टाचार के विरुद्ध पहली पहल है। नोटबंदी को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए हमें रचनात्मक तरीके अपनाने होंगे। नीतियों से सिर्फ सोच को दिशा मिलती है, उनको परचम तक पहुंचाने के लिए नीयत की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। भारत के पास राजनीतिक नीयत है, निपुण नीति निर्माता हैं, और 1.25 करोड़ नागरिकों का सहयोग है। जो नोटबंदी को सफल मानते हैं, उन्हें आर्थिक सफाई में निजी, पारिवारिक व सामाजिक स्तर पर और भी प्रयास करने होंगे। विपक्ष अगर नोटबंदी की तुलना नसबंदी से कर रहा है, तो स्वच्छ भारत की इस मुहीम को पूर्ण करने लिए सुझाव देने होंगे। कसीदे पढ़ने से देश नहीं चलता, और भाषण देने से बदलाव नहीं आता। ■